www.deshkiupasana.com
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र
RNI NO - UPHIN/2022/86937
जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE
सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 05 | अंक – 53 | जौनपुर, गुरुवार, 08 अक्टूबर 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

मेडिकल रिपोर्ट के नाम पर घूस लेते दलाल पकड़ा, चिकित्सक हिरासत में

जयपुर, (एजेंसी)। आठ अक्टूबर राजस्थान के भरतपुर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बृहस्पतिवार को 35 हजार रुपये की रिश्वत लेते एक दलाल को गिरफ्तार किया, जबकि रिश्वत मांगने के आरोपी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को भी हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसने नदबई थाने में मारपीट का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में उसके परिजनों की चोटों का मेडिकल परीक्षण राजकीय चिकित्सालय, नदबई में कराया जाना था। शिकायत के अनुसार, मेडिकल रिपोर्ट में 'हैवी एमएलसी' बनाने के बदले वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. शशिकान्त शर्मा द्वारा अपने कथित दलाल त्रिलोकचन्द शर्मा उर्फ चीनू के माध्यम से 35 हजार रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी। शिकायत के गोपनीय सत्यापन में रिश्वत की मांग की पुष्टि होने के बाद एसीबी ने जाल बिछाया। कार्रवाई के दौरान दलाल को 35,000 रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया गया। एसीबी के अनुसार, रिश्वत की राशि उसकी पैंट की जेब से बरामद की गई। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को उनके सरकारी आवास से हिरासत में लिया गया।

भारत में नेपाल और बांग्लादेश जैसी अराजकता फैलाना चाहती है कांग्रेस

नई दिल्ली, (एजेंसी)। आठ अक्टूबर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस सड़क पर किए जा रहे अपने प्रदर्शनों के जरिए देश में ''नेपाल और बांग्लादेश जैसी अराजकता'' फैलाने की कोशिश कर रही है क्योंकि राहुल गांधी सत्ता में आने के लिए ''बेताब'' हैं। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) के बुधवार के विरोध प्रदर्शन के कुछ वीडियो फुटेज दिखाते हुए कहा कि राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाद्रा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में पुलिसकर्मियों के साथ जिस तरह धक्का–मुक्की की, उससे पार्टी की मंशा साफ हो जाती है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा, ''कांग्रेस पार्टी की रणनीति भारत में नेपाल और बांग्लादेश जैसी अराजकता फैलाने की है।'' भंडारी ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का कथित वीडियो दिखाते हुए कहा, ''कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिसकर्मियों पर लात–घूंसों से हमला करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिसकर्मी वहां अपनी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उसे धक्का देता है और फिर लात मारता है।'' उन्होंने इसी तरह का एक अन्य वीडियो दिखाते हुए दावा किया कि पुलिसकर्मी राहुल गांधी से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अनुरोध कर रहे थे क्योंकि उनके साथ ''हजारों लोगों की भीड़'' थी।

डिजिटल इंडिया से खत्म हुआ डिजिटल डिवाइड, हर जिले तक पहुंचा 5जी - पीएम नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया पहल को टेक्नोलॉजी के लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक अहम कोशिश बताया। उन्होंने सरकार के इस लक्ष्य पर जोर दिया कि डिजिटल अंतर को खत्म किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि आधुनिक टेक्नोलॉजी सिर्फ साधन–संपन्न लोगों तक ही सीमित न रहे। 8 अक्टूबर को नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि इस बदलाव में मोबाइल फोन की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया पहल के जरिए हमने इस स्थिति को बदलने का संकल्प लिया, जिसमें मोबाइल फोन इस बदलाव के केंद्र में रहा। यह टेक्नोलॉजी के लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक बड़ी कोशिश रही है।

उन्होंने माना कि भारत को डिजिटल अंतर (डिजिटल डिवाइड) की चुनौती का सामना करना पड़ा है, जहाँ आधुनिक तकनीक तक पहुँच मुख्य रूप से उन्हीं लोगों के लिए संभव थी जो इसका खर्च उठा सकते थे। उन्होंने कहा कि पिछले 10–12 वर्षों में, मोबाइल फोन न केवल आधुनिक संचार के साधन के रूप में, बल्कि सुशासन के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में भी उभरा है। यह हमारे डिजिटल इंडिया विजन के केंद्र में रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में सुधार किए और तकनीक तक पहुँच को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार किया। उन्होंने कहा कि हमने इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया कि मोबाइल फोन और अन्य टेलीकॉम हार्डवेयर का निर्माण भारत में ही हो। देश भर में 5जी कनेक्टिविटी के विस्तार पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह तकनीक हर जिले तक पहुँच गई है और पूरे भारत में 5,50,000 से अधिक 5जी बेस स्टेशन काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि 2022 की तुलना में मोबाइल इंटरनेट की गति दस गुना बढ़ गई है।

गृह मंत्री अमित शाह ने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपनी और उनकी साथ वाली तस्वीरें शेयर करते हुए अमित शाह ने लिखा, ''महान भारतीय फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर का निधन कला की दुनिया के लिए एक अपूरणीय क्षति है। पांच दशकों से ज्यादा समय तक, अपनी स्वाभाविक एक्टिंग और दमदार डायलॉग डिलीवरी से उन्होंने दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। चाहे गंभीर सामाजिक मुद्दे हों या हास्य–व्यंग्य, उन्होंने जिस भी किरदार को निभाया, उसमें जान डाल दी। सूखे से प्रभावित किसान परिवारों की मदद के लिए 'नाम फाउंडेशन' के जरिए काम करना हो या सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए बॉर्डर पर जानाकृशोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद भी वे अपनी जड़ों से जुड़े रहे।''

अमित शाह ने एक्स पर आगे लिखा, ''जब भी मैं उनसे मिला, उनकी सादगी और स्पष्टवादिता ने हमेशा मुझ पर गहरा प्रभाव डाला। ईश्वर शोक–संतप्त परिवार और प्रशंसकों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें और दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें। ध शांति शांति शांति।'' पाटेकर को गोवा स्थित उनके घर पर गंभीर कार्डियक अरेस्ट हुआ। मेडिकल टीम उनकी चिकित्सा के लिए उनके घर पहुंची, लेकिन वह अचेत अवस्था में थे। इसके बाद उन्हें मणिपाल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां सुबह 5रू20 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नाना पाटेकर ने 75 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली।

राष्ट्रपति मुर्मु ने वायुसेना दिवस पर वायु योद्धाओं को दी बधाई

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज गुरुवार को वायुसेना दिवस पर भारतीय वायुसेना के जवानों को बधाई दी तथा कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' ने देश की सुरक्षा में वायु योद्धाओं के साहस, सटीकता और अभियानगत तैयारियों को प्रदर्शित किया। वायुसेना दिवस आठ अक्टूबर को भारतीय वायुसेना की स्थापना और वायु योद्धाओं के बलिदान की स्मृति में मनाया जाता है। राष्ट्रपति मुर्मु ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''वायुसेना दिवस पर सभी वायु योद्धाओं, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई। भारतीय वायुसेना ने पेशेवर दक्षता, अनुशासन और तैयारी के उच्च मानकों को कायम रखते हुए देश को अनुकरणीय सेवा दी है।'' उन्होंने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' ने देश की सुरक्षा में वायु योद्धाओं के साहस, सटीकता और

अभियानगत तैयारियों को प्रदर्शित किया। राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि इन योद्धाओं ने आपदाओं और मानवीय संकटों के दौरान भी महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। उन्होंने कहा, ''उनका समर्पण देश के लिए प्रेरणा और गौरव का स्रोत बना हुआ है। भारतीय वायुसेना अपनी सेवा और उत्कृष्टता की गौरवशाली विरासत को लगातार कायम रखे।

दलितों, वंचितों की प्रखर आवाज थे रामविलास पासवान, सीएम योगी बोले– चिराग बढ़ा रहे उनका मिशन

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी लखनऊ में गुरुवार को सुशांत गोल्फ सिटी में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की छठी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें नमन किया। इस दौरान भजन कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जुझारू तेवर वाले जननेता थे। उन्होंने अपने तेवर और संघर्ष से सामाजिक चेतना को नया आयाम दिया। करीब 50 वर्ष पहले बिहार में एक ऐसे युवा नेता का अभ्युदय हुआ, जो दलितों और वंचितों की प्रखर आवाज बने। बिहार की जनता ने उन्हें सर्वाधिक

मतों से जिताकर संसद भेजा। सीएम ने कहा कि बतौर सांसद उन्हें भी रामविलास पासवान के साथ लंबे समय तक संसद में कार्य करने का अवसर मिला। उनके मन में भारतीय परंपरा के प्रति हमेशा श्रद्धा और सम्मान का भाव रहा। दलित और वंचित वर्ग को न्याय मिले, उन्हें समाज की मुख्यधारा में सम्मान और उचित स्थान मिले, इसी संकल्प के साथ रामविलास पासवान ने निरंतर कार्य किया। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान की अनुपस्थिति आज भी खलती है, लेकिन संतोष इस बात का है कि उनके पुत्र चिराग पासवान उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कराने के लिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का आभार जताया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि रामविलास पासवान को बिहार में जो सम्मान मिला है, वही सम्मान उत्तर प्रदेश में भी दिलाया जाएगा।

जल जीवन मिशन व पोलावरम को गति देने के लिए केंद्र से समय पर फंड जारी करने की मांग - सीएम नायडू

नई दिल्ली, (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की और जल जीवन मिशन–अमरजीवी जलधारा कार्यों और पोलावरम परियोजना के लिए समय पर फंड जारी करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री नायडू ने पोलावरम परियोजना की प्रगति और हाल ही में 30,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए गए जल जीवन मिशन–अमरजीवी जलधारा कार्यों की जानकारी दी। पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश के एलुरु और पूर्वी गोदावरी जिलों में गोदावरी नदी पर स्थित एक प्रमुख बहुउद्देशीय राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना है। दो दिवसीय दिल्ली दौरे के तहत मुख्यमंत्री नायडू ने

सीआर पाटिल से मुलाकात की और बताया कि पोलावरम का काम तेज गति से चल रहा है, जिसका लक्ष्य अगले साल गोदावरी पुष्करम तक परियोजना को पूरा करके राष्ट्र को समर्पित करना है। यहां जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री नायडू ने केंद्रीय मंत्री से ओडिशा और छत्तीसगढ़ से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों को सुलझाने का भी आग्रह किया। उन्होंने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पोलावरम परियोजना के तहत ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बनने वाले सुरक्षात्मक तटबंधों के लिए लंबित जन सुनवाई के संबंध में जारी स्टॉप वर्क ऑर्डर को स्थायी रूप से वापस लेने का अनुरोध किया। हालांकि यह आदेश अभी स्थगित है, मुख्यमंत्री ने इसे स्थायी रूप से वापस लेने की मांग की। उन्होंने केंद्रीय मंत्रालय से ओडिशा और छत्तीसगढ़ सरकारों के साथ समन्वय करने और उन्हें जन सुनवाई प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मनाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री नायडू ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि सहयोग, समन्वय और लेनदेन की भावना से तीनों राज्यों के व्यापक हित में इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि पोलावरम में 41.15 मीटर कंटूर तक पानी रोकने के लिए जरूरी पुनर्वास और पुनर्स्थापन कार्यों में तेजी लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विस्थापित है।

गोवा के मुख्यमंत्री ने नाना पाटेकर के निधन पर जताया शोक, उनकी अनूठी अभिनय शैली को सराहा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गुरुवार को दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी विशिष्ट अभिनय शैली ने भारतीय सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है। 76 वर्षीय पाटेकर का बृहस्पतिवार तड़के पणजी के निकट डोना पाउला स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। सावंत ने सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर एक पोस्ट में रंगमंच तथा हिंदी और मराठी सिनेमा में पाटेकर के योगदान की सराहना की। प्रमोद सावंत ने कहा कि अभिनेता के निधन की खबर सुनकर वह ''स्तब्ध और बेहद दुखी'' हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, ''रंगमंच, हिंदी और मराठी सिनेमा में उनकी उल्लेखनीय यात्रा, दमदार अभिनय

और विशिष्ट कला ने भारतीय सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी।'' सावंत ने पाटेकर के परिवार, मित्रों, प्रशंसकों और पूरे फिल्म जगत के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा, ''ईश्वर उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे।

कृष्ण की बाल लीलाओं से भक्तिमय हुआ नोएडा, गोवर्धन पूजा में उमड़े श्रद्धालु

श्रीमद्भागवत कथा के पंचम दिवस भव्य छप्पन भोग का आयोजन, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का हुआ आगमन

ब्यूरो चीफ ध्सत्य प्रकाश उपाध्याय

नोएडा। सेक्टर–33 स्थित शिल्प हाट के निकट हेलीपैड ग्राउंड में भारत विकास परिषद, नोएडा की ओर से आयोजित श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के पंचम दिवस कथा पंडाल भक्ति और श्रद्धा से सराबोर नजर आया। कथा व्यास आचार्य मृदुल कांत शास्त्री जी महाराज ने भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं, गोवर्धन पर्वत धारण करने तथा गोवर्धन पूजा के प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण के लिए पहुंचे। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण विश्वविख्यात कथावाचक पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का आगमन रहा। उनके आगमन पर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। आयोजन के दौरान भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित भव्य छप्पन भोग भी लगाया गया। कथा प्रसंगों के माध्यम से आचार्य मृदुल कांत शास्त्री ने श्रद्धालुओं को भक्ति, संस्कार, सदाचार और सनातन जीवन मूल्यों का संदेश दिया। इससे पूर्व कथा के चौथे दिवस भगवान श्रीकृष्ण जन्म और भव्य नंदोत्सव का आयोजन हुआ था। श्रीकृष्ण जन्म की घोषणा होते ही कथा पंडाल जयकारों से गूंज उठा और श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर जन्मोत्सव मनाया। नंदोत्सव के दौरान भजन और मंगलगीतों पर श्रद्धालु भक्ति में झूमते नजर आए। कथा व्यास आचार्य मृदुल कांत शास्त्री जी महाराज ने पितृ पक्ष में श्रीमद्भागवत कथा श्रवण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भागवत कथा मनुष्य को भक्ति के साथ संस्कार, सदाचार और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाएं प्रेम, करुणा, आनंद और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश देती हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर जनपद न्यायाधीश, जिला गाजियाबाद भारत सिंह यादव सहित मनोज त्यागी, सीईओ संस्कार टीवी, रोहित रिछारिया महाराज, आचार्य सतपाल जी महाराज, आचार्य संगम जी महाराज और नोएडा की पूर्व विधायक विमला बाथम ने कथा व्यास का माल्यार्पण एवं शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया। कथा के मुख्य यजमान डॉ. वी.के. गुप्ता एवं श्रीमती रीना गुप्ता रहे। भारत विकास परिषद, नोएडा के अध्यक्ष संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आयोजन स्थल पर पेयजल,

पार्किंग, सुरक्षा और स्वच्छता की विशेष व्यवस्था की गई है। कथा के उपरांत प्रतिदिन भंडारा एवं प्रसाद वितरण भी किया जा रहा है। इस अवसर पर परिषद के सचिव अखिलेश भदौरिया, कोषाध्यक्ष अक्षय पारीक, महिला सहभागिता संयोजिका सुनीता मित्तल, पूर्व अध्यक्ष एवं संरक्षक डॉ. टी.एन. गोविल, शाखा संरक्षक प्रताप मेहता, सीए महेश बाबू गुप्ता, विपिन मल्हन, केशव गंगल, एन.के. अग्रवाल, रामरतन शर्मा, राकेश कत्याल, वीके सेठ, विकास अग्रवाल, डॉ. नरेश शर्मा, मुकुल वाजपेयी सहित परिषद के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

संपादकीय

विपक्षी खेमों से लगातार शक

जिस प्रक्रिया से 13 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, उस पर तीन में से दो निर्वाचन आयुक्तों का भी भरोसा नहीं रहा, तो नई मतदाता सूची की क्या विश्वसनीयता होगी?

मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) को जिस तरह आगे बढ़ाया गया, उस पर निर्वाचन आयोग के भीतर गहरे मतभेद थे। निर्वाचन आयुक्तों एस.एस. संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों के दौरान 14 बार अपनी गंभीर आपत्तियां दर्ज कराईं। एक अंग्रेजी अखबार की खोजी रिपोर्ट के मुताबिक इन आपत्तियों के तहत उन दोनों सदस्यों ने मतदाता सूची से नाम काटने और जोड़ने में मामले में उनको अंधेरे में रखने, नए वोटरों को जोड़ने की श्अनधि ाकृत्य प्रक्रिया अपनाने, तथा राज्यों के अधिकारियों को नजरअंदाज करते हुए सारे अधिकार श्दिल्ली में केंद्रित्य करने की शिकायत की। उन्होंने वोटर सॉफ्टवेयर की साख पर चिंता जताई। यहां तक कि अपनी शिकायतों को लेकर उन्होंने कैबिनेट सचिव का दरवाजा खटखटाया।

रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि एसआईआर को लेकर सार्वजनिक दायरों में जो संदेह और एतराज हैं, उन्हें आयोग के अंदर भी जताया गया। निर्वाचन आयोग के अंदर मतभेद के मामले पहले भी सामने आए हैं, लेकिन जिस स्तर पर एसआईआर के मामले में हुआ, वह अभूतपूर्व है। इसका अर्थ है कि सबकी आपत्तियों को ठुकराते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बुल्डोजरी अंदाज में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। ऐसा वे कैसे कर पाए और इसके लिए उन्हें कहां से ताकत मिली, इस पर अब स्वाभाविक कयास लगाए जाएंगे। जिस प्रक्रिया से 13 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, कई जगहों पर सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी से वैध नाम काटने के तथ्य सामने आए, और नए वोटर शामिल करने की प्रक्रिया पर विपक्षी खेमों से लगातार शक जताए गए, उस पर तीन में से दो निर्वाचन आयुक्तों का भी भरोसा नहीं रहा, तो आखिर नई मतदाता सूची की क्या विश्वसनीयता रहेगी? और क्या इनके आधार पर होने वाले चुनावों पर आम जन का यकीन बना रहेगा? ये अत्यंत गंभीर प्रश्न हैं। इसलिए इस पूरी मशक्कत को पलटने की जरूरत है। नई सूची रद्द कर पुरानी सूची अविलंब बहाल की जानी चाहिए। एसआईआर अगर जरूरी है, तो अब यह अनिवार्य हो गया है कि पहले इसकी प्रक्रिया पर सबको भरोसे में लेकर इसे दोबारा संपन्न किया जाए।

देश में मोदी विरोधी लहर शुरू हो चुकी है, अगर आज चुनाव हुए तो परिणाम क्या हो सकते हैं

नीरज

आज जब नरेंद्र मोदी सरकार के मुखिया के रूप में लगातार पच्चीस साल पूरे कर रहे हैं, तब भारतीय राजनीति की एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण तस्वीर सामने आ रही है। सात अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सरकार की कमान संभालने वाले नरेंद्र मोदी ने पहले गुजरात और फिर देश की सत्ता का नेतृत्व करते हुए बिना किसी अंतराल के पच्चीस वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह अपने आप में भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की असाधारण राजनीतिक यात्रा है। इस अवसर पर सत्ता पक्ष इसे नेतृत्व, सेवा, विकास और निरंतर जनविश्वास की उपलब्धि के रूप में देख रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष ठीक इसी समय चुनावी संस्थाओं की विश्वसनीयता, मतदाता सूची और लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर सरकार और चुनाव आयोग को घेर रहा है। यानी नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा के पच्चीसवें वर्ष का यह पड़ाव उस समय आया है जब सत्ता के सामने सबसे बड़ा सवाल शायद विपक्ष की ताकत का नहीं, बल्कि संस्थाओं और जनविश्वास का है। देखा जाये तो सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन स्वाभाविक रूप से उपलब्धियों को गिनाने का दिन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नरेंद्र मोदी के पच्चीस वर्ष के शासन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए उनके गुजरात के मुख्यमंत्रित्व और केंद्र की तीन लगातार सरकारों को सार्वजनिक विश्वास का प्रमाण बताया है। सरकार की ओर से कल्याणकारी योजनाओं, बुनियादी ढांचे, डिजिटल व्यवस्था, आर्थिक सुधार, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और तकनीकी उपलब्धियों को इस लंबे सफर की प्रमुख उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भी इस अवसर को सेवा और राष्ट्रहित के भाव से जोड़ा है। लेकिन राजनीति सिर्फ उपलब्धियों की सूची से नहीं चलती। देश की राजनीति का दूसरा चेहरा भी उतनी ही ताकत से दिखाई दे रहा है। छह अक्टूबर को राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में प्रदर्शन किया। संसद से चुनाव आयोग की ओर बढ़ते विपक्षी सांसदों को पुलिस ने रोका, जिसके बाद धरना, हिरासत और राजनीतिक टकराव की तस्वीरें सामने आईं। राहुल गांधी का बैरिकेड पर चढ़ना और "ज्ञानेश, इट्स डन ब्रो" जैसी युवा शैली की भाषा सोशल मीडिया पर तेजी से फैली। इस पूरे घटनाक्रम ने चुनाव आयोग और मतदाता सूची के विवाद को अचानक देश की राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया। विपक्ष इस पूरे विवाद को केवल मतदाता सूची की तकनीकी प्रक्रिया नहीं मान रहा। उसके लिए यह लोकतंत्र, मताधि ाकार और चुनावी निष्पक्षता का सवाल है। कांग्रेस और उसके सहयोगी आरोप लगा रहे हैं कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने से नागरिकों के मतदान अधिकार पर असर पड़ सकता है। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहा है और इस पूरे मामले को व्यापक राजनीतिक आंदोलन में बदलने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस लगातार चुनाव हारने के बाद चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा कर रही है और उसे अपनी राजनीतिक कमजोरी का जिम्मेदार संस्थाओं को बनाने के बजाय जनता का विश्वास जीतने की कोशिश करनी चाहिए। भाजपा का यह भी सवाल है कि जिस चुनावी व्यवस्था के माध्यम से विपक्ष कई राज्यों में जीत हासिल करता रहा, उसी व्यवस्था को अपनी हार के बाद अविश्वसनीय कैसे कहा जा सकता है यहीं से इस समय की राजनीति का सबसे बड़ा द्वंद्व सामने आता है। विपक्ष का सवाल है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न उठे तो लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा? सत्ता पक्ष का सवाल है कि बिना निर्णायक प्रमाण के चुनावी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने से क्या लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का भरोसा ही कमजोर नहीं होगा? दोनों पक्ष अपने–अपने तर्क रख रहे हैं, लेकिन एक तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर बहस अब महज विपक्षी भाषण नहीं रह गई है। हालांकि इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि विपक्ष के सारे आरोप सिद्ध हो चुके हैं। चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठना एक बात है और "चुनाव चोरी सिद्ध हो जाना" दूसरी बात है। शायद यही वह बिंदु है जहां से आम जनता और राजनीतिक विमर्श के बीच अंतर दिखाई देता है। राजनीति की दुनिया में इस समय ैप्, चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार सबसे बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहे हैं। समाचार चौनलों और सोशल मीडिया पर भी यही सबसे अधि ाक दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम व्यापक जनमत संकेतकों को देखते हैं तो तस्वीर कुछ अलग है। सितंबर 2026 के ताजा इप्सॉस सर्वेक्षण में सात में से लगभग सात भारतीयों ने माना कि देश सही दिशा में जा रहा है और करीब आठ में से आठ ने वर्तमान आर्थिक स्थिति को सकारात्मक माना है। लेकिन उसी सर्वेक्षण में बेरोजगारी भारत की सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। यानी देश के भविष्य को लेकर आशावाद मौजूद है, मगर नौकरी और अवसर को लेकर बेचौनी भी उतनी ही वास्तविक है। यही भारतीय जनमत की वर्तमान जटिलता है। जनता का एक बड़ा हिस्सा यह मान सकता है कि देश आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था टिकाऊ है, बुनियादी ढांचे में बदलाव आया है और भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत हुई है, लेकिन उसी व्यक्ति के घर में नौकरी, आमदनी, महंगाई और भविष्य की सुरक्षा की चिंता भी हो सकती है। सितंबर में शहरी उपभोक्ता विश्वास में भी सुधार आया और भारत का उपभोक्ता विश्वास सूचकांक बढ़ा। इसका मतलब यह हुआ कि आर्थिक तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक नहीं हैय फिर भी रोजगार सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। इससे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के सामने असली राजनीतिक प्रश्न भी स्पष्ट होता है। चुनौती केवल यह नहीं है कि विपक्ष कितना आक्रामक है। चुनौती यह है कि सरकार आर्थिक उपलब्धियों और बड़े राष्ट्रीय लक्ष्यों की कथा को आम नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी से कितना जोड़ पाती है। जब विकास का अर्थ सड़क, रेल, डिजिटल भुगतान और वैश्विक प्रतिष्ठा से आगे बढ़कर नौकरी, स्थिर आय और युवा के भविष्य में दिखाई देने लगेगा, तभी सरकारी उपलब्धियों का राजनीतिक असर और गहरा होगा। साथ ही नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत नेतृत्व को लेकर तस्वीर अभी भी पूरी तरह बदलती हुई नहीं दिखती। अगस्त 2026 के इंडिया टुडे–सी वोटर सर्वेक्षण में 48.7 प्रतिशत लोगों ने मोदी को अगले प्रधानमंत्री के लिए सबसे पसंदीदा विकल्प माना। हालांकि जनवरी के मुकाबले उनके समर्थन में कुछ कमी आई है। इस गिरावट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे सीधे मोदी विरोधी लहर भी नहीं कहा जा सकता। दूसरी ओर, राहुल गांधी अभी तक उस राजनीतिक बढ़त को हासिल नहीं कर पाए हैं, जो मोदी के समर्थन में कमी आने पर उन्हें स्वाभाविक रूप से मिल सकती थी। यानी मोदी की राजनीतिक ताकत अभी भी बनी हुई है, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दे रहा है।

मशीनरी से लेकर कर्मचारी बीमा तक, रिफॉर्म या फिर आने वाला है कोई स्टॉर्म

अभिनय

देश में व्यापार को आसान बनाने और टैक्सपेयर्स की सहूलियत के लिए सरकार ळैज 2.0 में बदलाव की तैयारी कर रही है। 8 अक्टूबर को होने वाली ळैज काउंसिल की बैठक में ई–वे बिल के नियमों को ढीला करने, गिरफ्तारी के डर को खत्म करने और सालों से फंसे हजारों करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट को जारी करने जैसे बढ़े बढ़े प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ळैज काउंसिल बुधवार को होने वाली अपनी बैठक में कई ऐसे प्रस्तावों पर विचार करेगी, जिनमें ई–वे बिल की जरूरतों से जुड़े नियमों को आसान बनाना और कानून के तहत गिरफ्तार करने की शक्तियों को हटाना शामिल है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि ये प्रस्ताव टैक्सपेयर से जुड़े सभी पहलुओं – जैसे रजिस्ट्रेशन, रिटर्न और रिफंड से लेकर इनपुट टैक्स क्रेडिट और कानूनी विवाद – को कवर करते हैं। ये प्रस्ताव ज़्यादा कागजी कार्रवाई वाले अनुपालनसे हटकर ऑटोमेटेड, डेटा–आधारित और जोखिम–आधारित प्रशासन की ओर बढ़ने का संकेत देते हैं। अगर जीएसटी काउंसिल इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है, तो गिरफ्तारी का फैसला अफसरों के हाथ में रहने के बजाय अदालत के अधीन हो जाएगा। वहीं, आपराधिक केस सिर्फ उन्हीं मामलों में दर्ज होंगे जो गंभीर और जानबूझकर की गई टैक्स चोरी से जुड़े होंगे। सबसे मुख्य प्रस्ताव इनपुट टैक्स क्रेडिट को आसान बनाने से जुड़ा है। इससे कंपनियों की फंसी हुई पूंजी छूटेगी और उद्योग जगत को एक अप्रत्यक्ष बढ़ावा मिलेगा। प्रस्तावों में कई ऐसे व्यापारिक इनपुट्स पर भी क्रेडिट देने की बात कही गई है जो अब तक ब्लॉक रोककर रखे गए थे। पिछले सितंबर में जीएसटी दरों के व्यापक युक्तिकरणके साथ इस बड़े सुधार की शुरुआत हुई थी, जिसने कारोबारियों और जीएसटी प्रणाली के बीच के तालमेल को पूरी तरह बदल दिया। इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव इनपुट टैक्स क्रेडिट को आसान बनाने का है, जिससे कंपनियों की फंसी हुई पूंजी मुक्त होगी और उद्योग जगत को एक अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिलेगा। जीएसटी काउंसिल प्लांट, मशीनरी और इनपुट सेवाओं पर चुकाए गए टैक्स को 5 वर्षों में मासिक किस्तों के रूप में वापस (रिफंड) करने पर विचार करेगी। वर्तमान में कंपनियां आईटीसी के तहत इस पूरी रकम की भरपाई नहीं कर पाती थीं। पहले जिन व्यावसायिक इनपुट पर क्रेडिट ब्लॉक था, अब उसका दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव है। टैक्स स्लैब में आने वाले कई उत्पाद (जैसे खाद्य पदार्थ, फार्मा, कपड़ा और इलेक्ट्रिक वाहन) इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (कच्चे माल पर ज्यादा टैक्स और तैयार माल पर कम टैक्स) का सामना कर रहे हैं। इसके कारण हजारों करोड़ रुपये का आईटीसी अटका हुआ है। इस पूंजी के जारी होने से उद्योग इसे फिर से पूंजीगत व्यय के रूप में निवेश कर सकेंगे। टेलीकॉम टावरों और पाइपलाइनों पर क्रेडिट मिलने से दूरसंचार, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, उर्वरक, गैस वितरण और बुनियादी ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) क्षेत्रों के भारी खर्च में बड़ी राहत मिलेगी।पहले यदि कोई सप्लायर टैक्स जमा नहीं करता था, तो उसका खामियाजा वास्तविक खरीदारको अपना क्रेडिट गंवाकर भुगतना पड़ता था। यह जीएसटी में विवादों का सबसे बड़ा कारण रहा है। अब यदि सौदा वैध है, तो खरीदार को आईटीसी रखने की अनुमति दी जाएगी और टैक्स वसूली सीधे डिफॉल्ट करने वाले सप्लायर से की जाएगी। चूंकि अब इनवॉइस–टू–इनवॉइस मिलान से खरीदार और विक्रेता का डेटा जुड़ा हुआ है, इसलिए सिस्टम फर्जी या बेमेल क्रेडिट को उसके स्रोत पर ही पकड़ सकता है।अब टैक्सपेयर्स को अधिकारियों द्वारा मैन्युअल जांच के लिए अलग से दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। कस्टम्स, आरबीआई के एक्सपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम और अन्य सरकारी प्रणालियों पर पहले से उपलब्ध डेटा को सीधे रिफंड प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाएगा।सेक्टर को बड़ी राहत मिल सकती हैय काउंसिल विदेशी ब्रांच ऑफिस को की गई सप्लाई को एक्सपोर्ट मानने पर विचार करेगी, जिससे ऐसे ट्रांजेक्शन के लिए योग्य हो जाएंगे। विदेशी खरीदारों को बेचे गए लेकिन यहीं किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डिलीवर किए गए सामान को भी एक्सपोर्ट माना जा सकता है, अगर पेमेंट विदेशी मुद्रा में किया जाए। नियमों को एक्सपोर्ट के पेमेंट मिलने से जुड़े के नियमों के साथ भी मिलाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित सुधारों का मकसद कम वैल्यू वाले मामलों में कंप्लायंस और कानूनी विवाद को कम करना भी है। सूत्रों ने बताया कि 10,000 से कम रकम वाले मामलों में कोई शो–कॉज नोटिस जारी नहीं किया जाएगा और यह बदलाव पेंडिंग मामलों पर भी लागू होगा। उन्होंने बताया कि रिटर्न में अंतर के कारण हर साल लगभग 95,000 नोटिस

जारी होते हैं, जबकि ऐसे नोटिस से होने वाली रिकवरी कुल रकम का सिर्फ 0.08% होती है। रू5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले और सिर्फ अनरजिस्टर्ड ग्राहकों को सप्लाई करने वाले छोटे बिजनेस को सालाना रिटर्न फाइल करने और तिमाही टैक्स पेमेंट करने की इजाजत दी जा सकती है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रस्ताव है, जिसके तहत ऑटोमेटेड रूट के लिए योग्य आवेदकों का रजिस्ट्रेशन तीन वर्किंग दिनों के भीतर हो जाएगाय इस प्रक्रिया में पहले से ही 61% रजिस्ट्रेशन शामिल हैं। ट्रेड नेम, डायरेक्टर या पार्टनर और अतिरिक्त बिजनेस एड्रेस में बदलाव भी ऑटोमैटिक प्रोसेसिंग के दायरे में आ सकते हैं।10,000 रुपये से कम के मामलो में कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। यह नया नियम पेंडिंग मामलों पर भी लागू करने का प्रस्ताव है। जिन छोटे कारोबारियों का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपये तक है और वे सिर्फ बिना–रजिस्टर्ड ग्राहकों को ही सामान बेचते है, उन्हें अब सालाना रिटर्न भरने और हर तिमाही टैक्स जमा करने की छूट मिल सकती है। कारोबार का रजिस्ट्रेशन आसान करने का भी प्रस्ताव है। ट्रेड नेम में बदलाव, नए बिजनेस एड्रेस जोड़ने जैसे बदलाव ऑटोमैटिक मंजूर हो सकते हैं

नई प्रदेश अध्यक्ष से उत्तर प्रदेश कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें

प्रदीप

योजनाएं खोजें कांग्रेस सिर्फ भाजपा–विरोधी वोटों पर निर्भर रहने के बजाय इंडिया गठबंधन में खुद को एक स्वतंत्र राजनीतिक ताकत के तौर पर पेश कर सकती है। नेतृत्व में बदलाव तभी असरदार होगा जब उसके साथ मजबूत जिला इकाइयां, बूथ–स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ता और भरोसेमंद उम्मीदवार भी हों। कोशिश ब्राह्मण वोटरों से दोबारा जुड़ने, किसी महिला नेता को ज़्यादा अहमियत देने और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पार्टी की स्थिति बेहतर करने की है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (यूपीसीसी) की अध्यक्ष के तौर पर आराधना मिश्र की नियुक्ति कांग्रेस की राजनीतिक पुररुत्थान की एक महत्वपूर्ण कोशिश है। इसके जरिए पार्टी अपने जातिगत गठबंधन आधार को फिर से बनाना चाहती है, समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ बातचीत में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है और 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए एक ज़्यादा भरोसेमंद संगठन तैयार करना चाहती है।चूंकि आराधना के राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, इसलिए यूपीसीसी अध्यक्ष के तौर पर उनके कार्यकाल में उन्हें पार्टी आलाकमान का पूरा समर्थन मिलेगा। जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के लिए एआईसीसी की प्रभारी थीं, तब आराधना मिश्र उनकी लगातार साथी रहीं और राज्य के अलग–अलग हिस्सों में उनके व्यापक दौरों के दौरान उन्हें अनुभव मिला। इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना और दूसरे समुदाय के नेताओं को आगे बढ़ाना इस रणनीति को और मजबूत करता है।आराधना मिश्र ब्राह्मण चेहरा हैं, जिन्हें विधायी कामकाज का अनुभव है। वह प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट से तीन बार विधायक रही हैं और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की बेटी हैं। वह ऐसे समय में एक प्रमुख ब्राह्मण चेहरा हैं जब कांग्रेस उन सवर्ण मतदाताओं के बीच अपना समर्थन फिर से हासिल करने की कोशिश कर रही है जो काफी हद तक भाजपा की ओर चले गए हैं। राज्य भर में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बावजूद अपनी सीट जीतने का उनका रिकॉर्ड उन्हें सिर्फ संगठनात्मक काम के लिए जाने जाने वाले नेता की तुलना में ज़्यादा भरोसेमंद बनाता है। कांग्रेस यह दिखाना चाहती है कि ब्राह्मण मतदाताओं के पास भाजपा के अलावा और भी राजनीतिक विकल्प हैं। हालांकि, ब्राह्मण नेता को नियुक्त करने से वे मतदाता अपने–आप वापस नहीं आएंगे। पार्टी को स्थानीय उम्मीदवार, एक भरोसेमंद राजनीतिक कार्यक्रम और जमीनी स्तर पर लगातार काम करने की जरूरत होगी।इसमें महिलाओं का भी एक पहलू है। महिला को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से कांग्रेस को महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर अपना दावा फिर से मजबूत करने का मौका मिलेगा, खासकर 2022 में उसके श्लड़की हूं, लड़ सकती हूंश अभियान के बाद। आराधना मिश्र को यूपीसीसी अध्यक्ष बनाने के बाद कांग्रेस नेतृत्व ब्राह्मण, मुस्लिम, ओबीसी और दलित प्रतिनिधित्व का एक व्यापक संयोजन बनाना चाहता है। एक मजबूत बातचीत करने वाली टीम बनाना उसका उद्देश्य है। आराधना मिश्र संगठन में तालमेल और सपा के साथ रिश्तों पर ध्यान दे सकती हैं, जबकि मसूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक अहम आवाज के तौर पर सामने आएंगे।कांग्रेस सिर्फ भाजपा–विरोधी वोटों पर निर्भर रहने के बजाय इंडिया गठबंध ान में खुद को एक स्वतंत्र राजनीतिक ताकत के तौर पर पेश कर सकती है। नेतृत्व में बदलाव तभी असरदार होगा जब उसके साथ मजबूत जिला इकाइयां, बूथ–स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ता और भरोसेमंद उम्मीदवार भी हों। कोशिश ब्राह्मण वोटरों से दोबारा जुड़ने, किसी महिला नेता को ज़्यादा अहमियत देने और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पार्टी की स्थिति बेहतर करने की है। इमरान मसूद को कार्यकारी अध यक्ष बनाने की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका राजनीतिक आधार कांग्रेस को एक अहम मुस्लिम नेता देता है। उनकी नियुक्ति यह भी संकेत देती है कि कांग्रेस सपा के साथ बातचीत में मजबूत रुख अपनाएगी।इसी तरह, देवेंद्र निषाद को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाना निषाद और नदी किनारे रहने वाले अन्य पिछड़े समुदायों तक पहुंचने की कोशिश है, जो उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर चुनावी तौर पर अहम हैं। एक और वरिष्ठ उपाध्यक्ष आलोक प्रसाद प्रभावशाली पासी दलित समुदाय से आते हैं। वह पासी वोटरों पर ध्यान देंगे जो अभी भी बसपा के साथ हैं। यहां यह बताना जरूरी है कि आराधना के पिता प्रमोद तिवारी, जो अब कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य हैं, ने अपनी रामपुर खास विधानसभा सीट से नौ बार जीतकर रिकॉर्ड बनाया था। प्रमोद तिवारी के मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। इसी समझ की वजह से समाजवादी पार्टी ने प्रमोद तिवारी के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। अगर समाजवादी पार्टी ने प्रमोद तिवारी के खिलाफ कोई उम्मीदवार उतारा भी, तो वह डमीया कमजोर उम्मीदवार होता था। इसीलिए प्रमोद तिवारी के लिए विधानसभा चुनाव जीतना हमेशा बहुत आसान होता था। इसमें कोई शक नहीं कि आराधना मिश्र के यूपीसीसी अध्यक्ष रहने से पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत करना आसान होगा। जब से आराधना मिश्र ने यूपीसीसी की कमान संभाली है, तब से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जाने–माने ब्राह्मण नेता कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। पवित्र शहर मथुरा से पूर्व मंत्री और जाने–माने ब्राह्मण नेता श्यामसुंदर शर्मा पार्टी में वापस आ गए हैं। ठाकुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार के काम करने के तरीके को लेकर प्रभावशाली ब्राह्मण समुदाय में काफी नाराजगी है। ब्राह्मण नेताओं और विधायकों ने कई बैठकें की हैं और सरकार पर ब्राह्मण समुदाय के प्रति उदासीनता बरतने का आरोप लगाया है।समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया है कि ठाकुर मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ब्राह्मणों को निशाना बना रही है और उन्हें परेशान कर रही है। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए ब्राह्मणों को लेकर लगाए गए आरोप राज्य में राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गए हैं। कांग्रेस तेजी से आगे बढ़ रही है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हाल ही में हुए गठबंधन से साफ है, जिसमें दोनों पार्टियां 10 विधानसभा सीटों पर सहमत हुई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राहुल गांध ी से मुलाकात की और घोषणा की कि उनकी अपना जनता पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होगी और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों में एनडीए के खिलाफ लड़ेगी।

नेक्स्ट-जेनरेशन जीएसटी और भारत के विकास का अगला चरण

निर्मला

विकसित भारत बनने के भारत के संकल्प के लिए एक ऐसी अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें हर स्तर और आकार के उद्यम फल–फूल सकें, चाहे उनकी शुरुआत कहीं से भी हुई हो। पिछले बारह वर्षों में हमारी सरकार ने इन अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण के लिए निरंतर कार्य किया है। वर्ष 2017 में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लागू होने से अप्रत्यक्ष कराधान के लिए एक साझा राष्ट्रीय ढांचा स्थापित हुआ। नेक्स्ट– जेनरेशन का जीएसटी नौ वर्षों के क्रियान्वयन तथा करदाताओं और राज्यों के अनुभवों के आधार पर इसी प्रयास को आगे बढ़ाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृ ष्टिकोण के अनुरूप, नेक्स्ट– जेनरेशन जीएसटी की परिकल्पना दो परस्पर जुड़े उद्देश्यों के साथ की गई थीरू कर दरों को कम व तर्कसंगत बनाना और अनुपालन को अधिक सरल बनाना। दरों में किए गए संशोधन 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हुए। प्रक्रियात्मक सुधारों का अगला चरण शीघ्र ही जीएसटी परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सम्मिलित रूप से, इन प्रयासों का उद्देश्य परिवारों को राहत देना, व्यवसायों को अधिक निश्चितता प्रदान करना और करदाताओं के लिए एक ऐसी प्रणाली सुनिश्चित करना है जिसमें वे बिना किसी अनावश्यक कठिनाई के अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। राज्य इस पूरी यात्रा में बराबर के साझेदार रहे हैं। वे परिषद में अपनी प्राथमिकताओं और अनुभवों को लेकर आए, निर्णयों को आकार देने में सहयोग किया और उनके क्रियान्वयन का दायित्व संभाला। मैं इस प्रतिबद्धता के लिए उनका आभार व्यक्त करती हूँ। जीएसटी की प्रगति प्रत्येक सरकार के उत्तरदायित्वों का सम्मान करते हुए एक साझा राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने की इसी तत्परता पर टिकी है। इसके परिणाम विश्वास को सुदृढ़ करते हैं। अक्टूबर 2025 से जुलाई 2026 के बीच, दर्ज की गई कर–योग्य आपूर्ति के मूल्य में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 25.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कर दरों की हल्की संरचना के साथ–साथ दर्ज आर्थिक गतिविधियों में भी व्यापक विस्तार देखा गया है। यह उस सुध ाार के लिए एक अत्यंत उत्साहवर्धक आधार है जिसका उद्देश्य उद्यमों और सार्वजनिक वित्त दोनों को संबल प्रदान करना है। यह सुदृढ़ता हालिया राजस्व आंकड़ों में स्पष्ट दिखाई देती है। अप्रैल–सितंबर 2026 के दौरान सकल जीएसटी संग्रह 12.46 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि से 11.6 प्रतिशत अधिक है। जून से सितंबर तक के प्रत्येक महीने में वार्षिक आधार पर दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की गईय इन चार महीनों का कुल संग्रह मिलकर लगभग 15 प्रतिशत की गति से बढ़ा। कर वापसी (रिफंड) के बाद शुद्ध संग्रह में भी इस छमाही के दौरान 10.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार, करदाताओं को दी गई राहत और विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि साथ–साथ हुई है। इस विस्तार का दायरा उसके पैमाने जितना ही महत्वपूर्ण है। सभी 11 क्षेत्रक समूहों और सभी प्रमुख राज्यों में दर्ज कर–योग्य आपूर्ति में वृद्धि देखी गई। भारत जैसी विविध अर्थव्यवस्था में यह व्यापक प्रसार अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक हिस्सों में होने वाली यह वृद्धि अधिक से अधिक व्यवसायों को विस्तार लेते बाजारों में भाग लेने का अवसर देती है, और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न मांग, निवेश तथा रोजगार से अधिकाधिक समुदायों को लाभान्वित करती है। सुधार के बाद की अवधि की तुलना में उपभोक्ताओं को की गई प्रत्यक्ष बिक्री (बी2सी) में भी 26.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। जब कर राहत का प्रभाव कीमतों में दिखाई देता है, तो परिवारों के पास अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने या बचत करने के लिए अधिक गुंजाइश होती है। उपभोक्ता राहत और उद्यम विकास आपस में गहराई से जुड़े हैंरू परिवारों की क्रय शक्ति व्यवसायों द्वारा दी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मांग को बनाए रखती है। इसका लाभ परिवार से लेकर खुदरा विक्रेता, आपूर्तिकर्ता और उत्पादक तक सभी तक पहुंचता है। लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक राष्ट्रीय बाजार तभी सार्थक होता है जब वह उनके स्थानीय परिवेश से परे ग्राहकों तक पहुँचने का व्यावहारिक मार्ग प्रशस्त करे। द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों के व्यवसायों को स्थानीय स्तर पर निवेश और रोजगार जारी रखते हुए ऐसे संबंध बनाने में सक्षम होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर, इन शहरों में विस्तार करने वाले उद्यम स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं और वितरकों के लिए नए अवसर सृजित कर सकते हैं। जीएसटी का साझा ढांचा इन कड़ियों को सुदृढ़ करता हैय और सरल प्रशासनिक व्यवस्था को इन्हें बनाए रखना और भी सहज बनाना होगा। इस व्यवस्था में सहभागिता अत्यंत व्यापक रही है। अगस्त के अंत तक केंद्र और राज्य क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत कुल जीएसटी पंजीकरण लगभग 1.71 करोड़ तक पहुंच गए, जो एक वर्ष पहले की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक हैं। अप्रैल–जुलाई 2026 की कर अवधियों के लिए, निर्धारित तिथि तक दाखिल किए गए।

दुर्गा पूजा की तैयारियां समय से पूरी करने का डीएम ने दिया निर्देश किसी दुर्घटना की स्थिति में संबंधित अधिकारी होंगे जिम्मेदार –डीएम

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में दुर्गा पूजा एवं आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन. की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में त्योहारों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग को क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और पैचिंग कराने, जल निगम को खुले सीवर एवं मैनहोल के ढक्कन बंद कराने तथा विद्युत विभाग को जर्जर तार और खंभे बदलने के निर्देश दिए। नगर पालिका को जलभराव रोकने के साथ प्रमुख मार्गों, पूजा पंडालों और विसर्जन स्थलों पर पर्याप्त प्रकाश एवं सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने विसर्जन मार्गों और स्थलों की तैयारियां पहले से पूरी कराने तथा त्योहारों के दौरान मोबाइल शौचालय की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि किसी दुर्घटना की स्थिति में संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। बैठक में शांति समिति के सदस्यों ने सड़क, बिजली, कूड़ा उठान, सुरक्षा और यातायात से जुड़ी समस्याएं रखीं, जिस पर डीएम ने त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। सदस्यों ने एआई के माध्यम से भ्रामक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने की जानकारी दी। डीएम ने ऐसे मामलों की निगरानी, तथ्यात्मक जांच और दोषियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए। पूजा समितियों को पंडालों में प्रवेश–निकास की उचित व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रखने और स्वयंसेवक तैनात करने को कहा गया। हाईटेंशन तारों के नीचे पंडाल नहीं लगाने तथा अग्निशमन यंत्र और विद्युत सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व परमानंद झा, मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अंबष्ट, नगर मजिस्ट्रेट सहित संबंधित अधिकारी, पूजा समितियों के पदाधिकारी और शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे।

आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड ने लॉन्च किया 'आकाश इनविक्टस इंजीनियरिंग 2.0', इनविक्टस के हाई-परफॉर्मेंस एकेडमिक आर्किटेक्चर के साथ जेईई इकोसिस्टम को करेगा मजबूत

लखनऊ। भारत की प्रमुख परीक्षा–तैयारी संस्थाओं में से एक, आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड ने आकाश इनविक्टस इंजीनियरिंग 2.0 के माध्यम से इंजीनियरिंग की तैयारी के अपने अकादमिक इकोसिस्टम को और मजबूत करने की घोषणा की है। यह नया परफॉर्मेंस आधारित एकेडमिक सिस्टम जेईई मेन, जेईई एडवांस्ड और स्टेट सीईटी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक व्यवस्थित और बेहतर तैयारी का मार्ग तैयार करेगा।

छह मजबूत स्तंभों पर आधारित 360–डिग्री तैयारी का अनुभव

विद्यार्थियों को इनविक्टस का अलग अनुभव हर स्तर पर देखने को मिलेगा चाहे वह क्लासरूम में सीखने की प्रक्रिया हो, स्टडी मटेरियल और किताबें हों, टेस्ट हों या उन्हें मिलने वाली मेंटरशिप। यह कार्यक्रम छह प्रमुख स्तंभों पर आधारित हैरू

परिणाम–केंद्रित अकादमिक दृष्टिकोणरू हर कक्षा, प्रैक्टिस सेशन और रिवीजन साइकिल को एक ही लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जेईई एडवांस्ड, जेईई मेन, बिट्सैट और विभिन्न राज्यों की इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में विद्यार्थियों को सर्वश्रेष्ठ संभव रैंक दिलाना।

रैंक–प्रमाणित फैकल्टी टीम'– फैकल्टी टीम आकाश इनविक्टस की सबसे बड़ी ताकत है। इसी अनुभवी अकादमिक टीम ने इनविक्टस के पाठ्यक्रम, स्टडी मटेरियल और टेस्टिंग सिस्टम को एक नई ऊँचाई दी है।

वैज्ञानिक तरीके से तैयार और शोध–आधारित स्टडी मटेरियल– इन किताबों को इसी अकादमिक टीम ने लर्निंग साइंस और परीक्षा के पैटर्न पर किए गए गहन शोध के आधार पर नए सिरे से तैयार किया है। यह विद्यार्थियों को बुनियादी अवधारणाओं से लेकर सबसे कठिन प्रश्नों तक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने में मदद करता है।

स्मार्ट टेस्टिंग और गहन विश्लेषण– टेस्टिंग की आवृत्ति, गहराई और स्तर तीनों को नए सिरे से तैयार किया गया है। हर टेस्ट के बाद विद्यार्थियों को अपनी मजबूतियों, कमियों और सुधार की जरूरत वाले सटीक क्षेत्रों की स्पष्ट तस्वीर मिलती है।

एक ट्रांसपेरेंट ग्रोथ मैप– स्टूडेंट्स और पेरेंट्स साफ देख सकते हैं कि स्टूडेंट आज कहां खड़ा है और वह कहां पहुंचना चाहता है।

कक्षा के बाहर मेंटरशिप और इकोसिस्टमरू जोसा काउंसलिंग गाइडेंस, डाउट सपोर्ट और गाइडेंस सहित लगातार मेंटरशिप जो क्लासरूम के घंटों के बाद भी स्टूडेंट के साथ रहती है, ताकि कोई भी स्टूडेंट पीछे न छूट जाए।

नेशनल लॉन्च के साथ, आकाश इनविक्टस चार खास बैच भी पेश कर रहा है ऐस, अचीवर, एक्सेलेरेटर, और एपेक्स।हर बैच एक जैसा मजबूत रास्ता है, जो इस बात पर बना है कि कोई स्टूडेंट सबसे अच्छा कैसे सीखता है और उसकी ख्वाहिश क्या है। चारों का मकसद एक ही हैरू यह पक्का करना कि हर स्टूडेंट बिना टेंशन के अपनी पूरी काबिलियत तक पहुँचे।

लॉन्च पर बात करते हुए, आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ

एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, श्री चंद्र शेखर रेड्डी गरिसा ने कहा– आकाश इनविक्टस–इंजीनियरिंग 2.0 को हमारे सबसे अच्छे टीचरों ने बनाया है, जिनके पास हर साल टॉप रैंक लाने का दशकों का अनुभव है। उन्होंने हमारे करिकुलम को फिर से बनाया, हमारी किताबें फिर से लिखीं, और हमारे टेस्टिंग मैकेनिज्म को शुरू से ही रीडिजाइन किया। हमने पहले कुछ खास सेंटर्स पर प्रोग्राम चलाया, और जेईई 2026 में रिजल्ट शानदार रहे। आज, हम भारत में हर आकाश ब्रांच के हर स्टूडेंट के लिए आकाश इनविक्टस ला रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमारे मौजूदा स्टूडेंट्स से होगी। हमारा मानना घ्है कि यह सिस्टम हमारे स्टूडेंट्स को जेईई एडवांस्ड, जेईई मेन, बिटसैट, और स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम में अपनी सबसे अच्छी रैंक पाने में मदद करेगा और हमें यकीन है कि जेईई 2027 और 2028 आकाश के इतिहास में सबसे अच्छे रिजल्ट होंगे। आखिर "एक्सीलेंस एक्सक्लूसिव क्यों रहना चाहिए।"

यह रोलआउट पूरे भारत में आकाश की सभी ब्रांच में होगा और तुरंत शुरू हो जाएगा। आकाश के मौजूदा स्टूडेंट्स सबसे पहले इनविक्टस सिस्टम में जाएंगे, उसके बाद हर नया स्टूडेंट जो जुड़ेगा। ब्रांच स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए ओरिएंटेशन सेशन भी कर रही हैं ताकि इस प्रोग्राम को डिटेल में समझने में मदद मिल सके।

पीयू के दो शिक्षक विश्व के शीर्ष दो प्रतिशत वैज्ञानिकों में शामिल

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के दो शिक्षकों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया है। इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संकाय के संकायाध्यक्ष प्रो. सौरभ पाल और रज्जू भैया संस्थान के रसायन विज्ञान विभाग के सहायक आचार्य डॉ. मिथिलेश यादव को विश्व के शीर्ष दो प्रतिशत प्रभावशाली वैज्ञानिकों की प्रतिष्ठित सूची में स्थान मिला है। यह सूची स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और एल्सेवियर द्वारा वैज्ञानिकों के शोध योगदान के विभिन्न मानकों के आधार पर जारी की जाती है। प्रो. सौरभ पाल कंप्यूटर एप्लीकेशन विभाग में प्रोफेसर हैं। वे डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग और हेल्थकेयर एनालिसिस के क्षेत्र में शोध कर रहे हैं। 25 वर्षों से अधिक के शोध अनुभव वाले प्रो. पाल वर्ष 2001 से विश्वविद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं। उनके 120 से अधिक अंतरराष्ट्रीय शोध पत्र और 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनके शोध कार्यों को 6,826 से अधिक गूगल साइटेशन मिले हैं। उनका एच–इंडेक्स 38 और आई10–इंडेक्स 66 है। उनके निर्देशन में छह शोधार्थी पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं, जबकि छह अन्य शोधार्थी शोधरत हैं। डॉ. मिथिलेश यादव लगातार छठी बार इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल हुए हैं। पॉलीमर संश्लेषण एवं अनुप्रयोग के क्षेत्र में 16 वर्षों से अधिक का शोध अनुभव रखने वाले डॉ. यादव के 80 से अधिक अंतरराष्ट्रीय शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। उन्हें 3,894 से अधिक गूगल साइटेशन मिले हैं और उनका एच–इंडेक्स 33 है। वे अंतरराष्ट्रीय जर्नल 'च्वसलउमते के संपादक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं तथा बायोपॉलिमर नैनोकम्पोजिट्स पर शोध कर रहे हैं। वे दक्षिण कोरिया और ताइवान में वरिष्ठ शोधकर्ता के रूप में कार्य कर चुके हैं तथा जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली में कोठारी पोस्ट–डॉक्टरल फेलो रह चुके हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राकेश कुमार सिंह ने दोनों शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि पूरे विश्वविद्यालय परिवार के लिए गौरव का विषय है। इससे विश्वविद्यालय के शिक्षकों और शोधार्थियों को उच्च स्तरीय अनुसंधान के लिए प्रेरणा मिलेगी। विश्वविद्यालय के कुलसचिव विनोद कुमार सिंह सहित अन्य शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने भी दोनों वैज्ञानिकों को बधाई दी।

टीबी मुक्तभारत अभियान में जौनपुर में 'जॉश' टीम लॉन्च

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बुधवार को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से 'टीबी मुक्त भारत' अभियान के अंतर्गत ज्वाइंट स्क्वाड फॉर हेल्थ (जॉश) टीम का शुभारंभ किया गया। भारत मंडपम, नई दिल्ली से आयोजित कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण जौनपुर में भी किया गया। जिलाधिकारी के नेतृत्व में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने वर्चुअल माध्यम से सहभागिता की। कार्यक्रम में टीबी उन्मूलन अभियान को जन–जन तक पहुंचाने और समुदाय की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। बताया गया कि जनपद के ग्रामों, नगर पंचायतों एवं वार्डों में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा के लिए खंड विकास अधिकारियों तथा अधिशासी अधिकारियों के स्तर से सहयोग लिया जाएगा। इसके साथ ही एनएसएस, एनसीसी और भारत वॉलंटियर्स को जोड़कर 'जॉश' टीम का गठन किया गया है। टीम अपने–अपने क्षेत्रों में टीबी मरीजों को सहयोग देने के साथ समुदाय को बीमारी के प्रति जागरूक करेगी। टीम के सदस्य टीबी मरीजों को उपचार जारी रखने के लिए प्रेरित करने, सरकार की योजनाओं की जानकारी देने तथा ग्राम पंचायतों एवं वार्डों को टीबी मुक्त बनाने के प्रयासों में सहयोग करेंगे। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. गंगाराम गौतम, एसडीएम सदर शिव प्रताप, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रभात कुमार, डॉ. आलोक सिंह, डॉ. अरुण भारती, डॉ. अरुण यादव सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. सुशील अग्रहरि ने किया। समन्वयक सलिल कुमार, राजीव कुमार, सुरेंद्र कुमार, लोकेश कुमार, संजय और नितिन कुमार सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

एसकेडी एकेडमी एवं एसकेडी इंटरनेशनल स्कूल में मनाया गया 94वां भारतीय वायुसेना दिवस

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। एसकेडी एकेडमी एवं एसकेडी इंटरनेशनल स्कूल की सभी शाखाओं में 94वां भारतीय वायुसेना दिवस बड़े उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विशेष प्रार्थना सभा से हुई, जिसमें विद्यार्थियों ने भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास पर भाषण, कविताएँ और देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने प्रश्नोत्तरी, पोस्टर निर्माण एवं विमान मॉडल निर्माण गतिविधियों में भाग लिया, वहीं नन्हे विद्यार्थी पायलट और वायुसेना अधिकारियों की वेशभूषा में नजर आए। विद्यार्थियों को वायुसेना के ध्येय वाक्य ष्नभः स्पृशं दीप्तम्ष् के अर्थ से भी परिचित कराया गया। एसकेडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के निदेशक मनीष सिंह ने कहा, ष्भारतीय वायुसेना साहस और राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक है। ऐसे आयोजन हमारे विद्यार्थियों को ऊँचे लक्ष्य रखने और गर्व के साथ देश की सेवा करने की प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान एवं देश के वीर वायु योद्धाओं को सलामी के साथ हुआ।

राहुल–प्रियंका के हिरासत में लिए जाने से आक्रोशित कांग्रेस का मार्च चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बर्खास्तगी की किया मांग

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह के नेतृत्व में पैदल विरोध मार्च निकाला मार्च महात्मा गांधी की प्रतिमा से शुरू होकर अंबेडकर तिराहे होते हुए कलेक्ट्रेट स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें बर्खास्त कर जेल भेजने की मांग की। निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर कांग्रेसियों ने कथित वोट चोरी के मुद्दे पर विरोध जताया। जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सत्ता के इशारे पर करोड़ों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाकर लोकतंत्र और संविधान को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने ज्ञानेश कुमार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आरिफ खान ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी कर केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को संरक्षण देने का काम किया है। उन्होंने कथित वोट चोरी के मामले में कार्रवाई की मांग की। विरोध मार्च का संचालन जिला उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी राकेश मिश्रा ने किया। इस दौरान इंटक के प्रदेश चेयरमैन डॉ. परमेंदर सिंह, डॉ. आरसी पांडेय, अनिल दूबे आजाद, राकेश सिंह डब्बू, विनय तिवारी, गौरव सिंह शनी, वरुणा शंकर चतुर्वेदी, शिव मिश्रा, नसीम, मुहम्मद वकील, कृष्ण चंद निषाद, लाल प्रकाश पाल, नीलेश सिंह, इरशाद खान, इकबाल हुसैन, विजय बहादुर यादव, शैलेन्द्र यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास के क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात रहा।

मानसिक स्वास्थ्य के बिना अधूरा है शारीरिक स्वास्थ्य – प्रो. अजय प्रताप सिंह

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के व्यावहारिक मनोविज्ञान विभाग द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अंतर्गत आयोजित तीन दिवसीय मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का गुरुवार को शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के प्रथम दिन शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय के मुक्तांगन में मानव श्रृंखला बनाकर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, संवेदनशीलता और समाज में सकारात्मक बदलाव का संदेश दिया।

व्यावहारिक मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रो. अजय प्रताप सिंह ने कहा कि मन और शरीर का संबंध समग्र स्वास्थ्य का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकता है, लेकिन यदि उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वह अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी पूर्ण लाभ नहीं उठा सकता। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एक–दूसरे से गहराई से जुड़े हैं तथा दोनों एक–दूसरे को प्रभावित करते हैं।

उन्होंने कहा कि अनेक शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं पर माइंड–बॉडी रिलेशन का प्रभाव पड़ता है। इसलिए स्वस्थ एवं संतुलित जीवन के लिए मानसिक स्वास्थ्य को भी शारीरिक स्वास्थ्य के समान महत्व दिया जाना आवश्यक है।

सहायक आचार्य डॉ. अन्नू त्यागी ने कहा कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो मानसिक स्वास्थ्य की वैश्विक महत्ता को दर्शाता है। उन्होंने विद्यार्थियों को अपनी भावनाओं और मानसिक स्थिति को समझने, अपनी समस्याओं पर खुलकर बात करने तथा आवश्यकता पड़ने पर परिवार, मित्रों या विशेषज्ञों से सहयोग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष की थीम "जीवन के अनुभवों को सुना जाएरू वास्तविक आवाज, वास्तविक बदलाव" को केंद्र में रखते हुए तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

सहायक आचार्य डॉ. जाह्नवी श्रीवास्तव ने कहा कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य भी स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने बताया कि इसी उद्देश्य से विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने विद्यार्थियों से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में सहभागिता करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में उज्मा खान, संजीव कुमार यादव, प्रीती सिंह, उमम अंसारी, शम्भू नाथ, संतोष, पंकज सिंह सहित विभिन्न विभागों के विद्यार्थी उपस्थित रहे।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान में बाधा से पेंशनर्स परेशान समस्या दूर नहीं हुई तो अनशन और धरना-प्रदर्शन की चेतावनी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की जनपद शाखा की मासिक बैठक गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पेंशनर्स कार्यालय में जिलाध्यक्ष सीबी सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों के भुगतान में आ रही समस्याओं पर चिंता जताई गई और शीघ्र समाधान की मांग की गई। जिलाध्यक्ष सीबी सिंह ने कहा कि शासन स्तर से 30 सितंबर तक चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों के लिए ऑफलाइन तथा एक अक्टूबर से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से व्यवस्था निर्धारित की गई है। इसके बावजूद मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर पर 30 सितंबर तक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों को तकनीकी परीक्षण के लिए 25 सितंबर से ही लेना बंद कर दिया गया है। उन्होंने इसे शासनादेश के विपरीत बताते हुए तत्काल व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि समस्या का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो एसोसिएशन संगठनात्मक कार्रवाई के साथ अनशन और धरना–प्रदर्शन करने को बाध्य होगा। उन्होंने हाल में हुए प्रांतीय कार्यक्रम के धरना–प्रदर्शन में पेंशनर्स की भागीदारी के लिए आभार जताते हुए आगामी संघर्ष के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पूर्व अध्यक्ष एवं संरक्षक राकेश कुमार श्रीवास्तव ने केंद्र सरकार से आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के संकल्प पत्र में पेंशनर्स के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को तत्काल शामिल करने की मांग की। बैठक में सदस्यों ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति से जुड़ी कठिनाइयां रखीं और सरकार से समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की मांग की। बैठक का संचालन जिलामंत्री कृपाशंकर उपाध्याय ने किया।

इस अवसर पर ओंकार नाथ मिश्र, कांति सिंह, कृष्ण कुमार त्रिपाठी, चंद्रशेखर सिंह, अशोक कुमार मौर्य, सुबेदार यादव, प्रमोद कुमार सिंह, राजेंद्र प्रसाद सिंह, राजेश कुमार श्रीवास्तव, डॉ. भारत यादव, वीवी सिंह, दिनेश चंद्र सिंह सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। अंत में स्व. ठकूरी यादव और स्व. दूधनाथ यादव के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई।

टीबी उन्मूलन अभियान से जुड़ेंगे युवा, निक्षय मित्र बनने की अपील

सुल्तानपुर । टीबी उन्मूलन अभियान को जन–जन तक पहुंचाने और युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी सभागार में बैठक आयोजित की गई। मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों के साथ मेरा युवा भारत (डल ठींतंज) के स्वयंसेवकों ने टीबी के खिलाफ जागरूकता अभियान को प्रभावी बनाने पर मंथन किया ।बैठक में सीएमओ डॉ. भारत भूषण, बीएसए उपेंद्र गुप्ता, जिला युवा अधिकारी सुधीर पांडेय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। माय भारत के मीडिया प्रभारी किशन पाठक समेत बड़ी संख्या में युवा स्वयंसेवकों ने भी सहभागिता की। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम से आयोजित लाइव कार्यक्रम में अधिकारियों और स्वयंसेवकों ने ऑनलाइन प्रतिभाग किया। इस दौरान टीबी उन्मूलन अभियान, जनभागीदारी और निक्षय मित्र योजना की जानकारी दी गई। लोगों से अधिक से अधिक संख्या में निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों को पोषण एवं सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराने की अपील की गई।

'गांव–गांव पहुंचाएंगे जागरूकता का संदेश'

माय भारत स्वयंसेवकों को अपने क्षेत्रों में युवाओं और आमजन को टीबी के लक्षण, जांच, उपचार और बचाव के प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि टीबी उन्मूलन केवल सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग की सहभागिता से ही यह अभियान सफल होगा।

'सीडीओ ने दिलाई नशा मुक्त भारत की शपथ'

बैठक के दौरान सीडीओ विनय कुमार सिंह ने अधिकारियों, कर्मचारियों और उपस्थित लोगों को नशा मुक्त भारत के निर्माण की शपथ दिलाई। उन्होंने युवाओं से नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और दूसरों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। अंत में "टीबी हारेगा, देश जीतेगा" के संदेश के साथ लोगों से अभियान में सक्रिय भागीदारी करने तथा जरूरतमंद टीबी मरीजों के सहयोग के लिए निक्षय मित्र बनने की अपील की गई।

एनएचएम कर्मियों ने तीन दिवसीय हड़ताल का किया ऐलान

सुल्तानपुर। राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं जिला चिकित्सालय सुल्तानपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत कार्यरत आयुष चिकित्सकों समेत विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों ने प्रदेश कार्यकारिणी के दिशा–निर्देश पर कार्य बहिष्कार करते हुए तीन दिवसीय हड़ताल की घोषणा की है। कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार से शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है। एनएचएम कर्मियों की प्रमुख मांगों में 10 वर्ष या उससे अधिक समय से सेवा दे रहे सभी एनएचएम अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लॉयल्टी बोनस देकर नियमित किए जाने, समान कार्य के लिए समान वेतन लागू करने तथा कर्मचारी और उसके परिवार को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग शामिल है। कर्मचारियों ने मौजूदा महंगाई को देखते हुए महंगाई भत्ता (डीए) देने, ईपीएफ, एचआरए और ग्रेच्युटी की सुविधा लागू करने तथा सेवा के दौरान मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की भी मांग उठाई है। इसके साथ ही नियमित पदों पर होने वाली भर्तियों में एनएचएम कर्मियों के लिए कोटा निर्धारित करने की मांग भी प्रमुखता से रखी गई है। कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, बावजूद इसके उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान सुविधाएं और अधिकार नहीं मिल रहे हैं। एनएचएम कर्मियों ने सरकार से सभी मांगों पर सकारात्मक एवं शीघ्र निर्णय लेने की अपील की है। कर्मचारियों का कहना है कि मांगों के समाधान तक आंदोलन को प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देशानुसार आगे बढ़ाया जाएगा।

'जनसुनवाई में 42 शिकायतें मिलीं'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' जिलाधिकारी राहुल पाण्डेय ने गुरुवार को जन सुनवाई के दौरान जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आये फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। जनसुनवाई के दौरान कुल 42 शिकायतें प्राप्त हुईं।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समय–सीमा में गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा फरियादियों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार, उप जिलाधिकारी न्यायिक आशुतोष, सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

मार्च 2027 में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों की सूची जारी करने की मांग

सुल्तानपुर। बेसिक शिक्षा परिषद एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत उन शिक्षकों की सूची शीघ्र जारी करने की मांग उठी है, जो मार्च 2027 में अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले हैं। शिक्षक नेता रणवीर सिंह ने इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेन्द्र गुप्ता से सूची तत्काल जारी किए जाने की मांग की है। शिक्षक नेता रणवीर सिंह ने कहा कि शासन के निर्देशों के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों की सूची निर्धारित समय से लगभग छह माह पूर्व जारी किया जाना आवश्यक है। इससे संबंधित शिक्षकों को विद्यालय का संपूर्ण चार्ज व्यवस्थित रूप से हस्तांतरित करने, अपनी सेवा संबंधी पत्रावलियों को समय से पूर्ण कराने तथा सेवानिवृत्ति से जुड़े देयकों एवं पावनों की पत्रावली तैयार कराकर संबंधित अधिकारियों को समय से प्रेषित कराने में सुविधा मिलती है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी होने से शिक्षकों को अनावश्यक भागदौड़ और कार्यालयों के चक्कर लगाने से भी राहत मिलेगी। साथ ही पेंशन, जीपीएफ, ग्रेच्युटी सहित अन्य देयकों के निस्तारण की प्रक्रिया भी समय से आगे बढ़ाई जा सकेगी। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेन्द्र गुप्ता ने बताया कि संबंधित पटल सहायक को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। मार्च 2027 में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों की सूची जल्द ही जारी कर दी जाएगी।

तहसील मुख्यालय की बेशकीमती सरकारी जमीनों पर रसूखदारो का अवैध कब्जा

सुलतानपुर। तहसील मुख्यालय बल्दीराय में करोड़ों रुपये कीमत की बेशकीमती सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जों का मामला एक बार फिर सवालों के घेरे में है। आरक्षित तालाब, नवीन परती, घूर गड्ढा, ट्यूबवेल सड़क, खलिहान और बंजर भूमि जैसी सार्वजनिक उपयोग की जमीनों पर कब्जे की शिकायतें सामने आ रही हैं। आरोप है कि तहसील प्रशासन द्वारा जुर्माना लगाने और बेदखली की कार्रवाई किए जाने के बावजूद कई स्थानों पर कब्जे नहीं हट सके हैं। सबसे गंभीर स्थिति बल्दीराय तहसील भवन के सामने पश्चिम दिशा में बताई जा रही है, जहां सरकारी भूमि पर कथित रूप से अवैध कब्जा कर आशियाना खड़ा कर लिया गया है। वहीं मुसाफिरखाना–देवरा मार्ग पर स्थित तालाब और खलिहान की बेशकीमती जमीन भी कब्जे के आरोपों से घिरी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सार्वजनिक उपयोग की इन जमीनों पर कब्जा होने से सरकारी संपत्ति का स्वरूप प्रभावित हो रहा है। मामले में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि यदि तहसील प्रशासन ने तहसील बल्दीराय मुख्यालय पर सरकारी भूमि पर कब्जा मानते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ जुर्माना और बेदखली की कार्रवाई की, तो उसके बाद भी कब्जा किस तरह कायम है क्या कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित रह गई या फिर बेदखली के बाद दोबारा कब्जा कर लिया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि तहसील की स्थापना के बाद अब तक कई एसडीएम आए और चले गए, लेकिन सरकारी भूमि को पूरी तरह कब्जामुक्त कराने की दिशा में स्थायी समाधान नहीं निकल सका। इससे प्रशासनिक कार्रवाई की प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तहसील के जिम्मेदार अधिकारी भी तहसील मुख्यालय पर सरकारी जमीन पर कब्जा करवाने में दोहरी रणनीति अपनाते है सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण की शिकायत पर पहले तो जिम्मेदार अधिकारी निर्माण पर रोक लगाते है फिर शुरू हो जाता है सेंटिंग का खेल मामले में जब पूर्ण रूप से सेटिंग हो जाती है तो वही रुका निर्माण पुनः शुरू करा दिया जाता है तहसील प्रशासन की इस रवैये मुख्यालय की ज्यादातर करोड़ो की कीमत की वेशकीमती सरकारी जमीन पर रसूखदारो का अनाधिकृत कब्जा हो गया है किन्तु तहसील के जिम्मेदार देखते हुए भी आंख बंद कर लिए है।बल्दीराय तहसील मुख्यालय पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन समय–समय पर अभियान चलाता है और राजस्व अभिलेखों के आधार पर कब्जेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। बावजूद इसके यदि उसी जमीन पर दोबारा निर्माण अथवा कब्जा बना रहता है तो यह राजस्व विभाग की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। स्थानीय नागरिकों की मांग है कि तहसील मुख्यालय की समस्त सरकारी भूमि तालाब, खलिहान, नवीन परती, घूर गड्ढा, बंजर, ट्यूबवेल सड़क की जमीन का राजस्व अभिलेखों से मौके पर सत्यापन कराया जाए। पूर्व में हुई बेदखली और जुर्माने की कार्रवाई की भी समीक्षा हो तथा जहां कब्जा पाया जाए, वहां नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जाए।

जनपद आगमन पर भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष का हुआ भव्य स्वागत

सुलतानपुर । नगर क्षेत्र के बलवंता मंदिर में भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष विशेश्वर राय का भव्य स्वागत किया कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि विशेश्वर राय ने कहा भारतीय मजदूर संघ देश का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन हैं यह श्रामिकों के पीड़ा को संवेदनशीलता के साथ जानता हैं आगरा में 20 अक्टूबर को सम्पन्न हुए 175 वी कार्य समिति बैठक में संघ 22 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक सूबे की राजधानी में बड़ा आंदोलन किया जाना सुनिश्चित किया हैं सोनभद्र के चुरक सीमेंट में लगभग तीन सौ श्रमिकों निकाल दिया जो भुखमरी के कगार पर हैं फैक्ट्री बंद हो गई उनका सेटलमेंट नहीं हुआ भारतीय मजदूर संघ ने इसके लिए भरपूर प्रयास किया सरकार में बैठे लोगों ने अभी तक अनसुना कर रखा हैं । दैनिक वेतन भोगी एवं सफाई कर्मचारियों के संगठन का निर्माण कार्य बी० एम० एस० का बैकों में खाता खोलने कार्य आगामी प्रदेश अधिवेशन में संख्या बल में सहभागिता संगठन विस्तार एंव सदस्यता पर जोर एवं धन संग्रह का कार्य। इस अवसर पर मुख्य रूप से दिनेश शुक्ला विभाग प्रमुख, दीपक मिश्रा जिलाध्यक्ष, शशांक मोहन शुक्ला जिलामंत्री, प्रेमचन्द श्रीवास्तव, नरेन्द्र मिश्रा, रंजना शर्मा, संगीता पांडेय, डा० संतोष श्रीवास्तव, अखिलेश सिंह, हरिविन्द्र सिंह समेत दर्जनों की संख्या में लोग उपस्थित रहे।

नवरात्रि–दशहरा को लेकर पुलिस अलर्ट, एसपी ग्रामीण ने घाटों का लिया जायजा

अयोध्या ।आगामी नवरात्रि, दुर्गापूजा एवं दशहरा पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं ।गुरुवार को एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राधेश्याम राय ने थाना गोसाईगंज क्षेत्र के प्रमुख घाटों एवं महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण किया ।इस मौके पर एसपी ग्रामीण राधेश्याम राय ने थानाध्यक्ष गोसाईगंज अभिमन्यु शुक्ला के साथ दिलासीगंज घाट, श्रृंगी ऋषि आश्रम घाट, सीताराम घाट और महादेवा घाट समेत अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का जायजा लिया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और कानून–व्यवस्था से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई ।निरीक्षण के दौरान एसपी ग्रामीण ने संबंधित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पर्वों के दौरान विशेष सतर्कता बरतने, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा कानून–व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए ।साथ ही महत्वपूर्ण स्थलों पर लगातार निगरानी रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल को मुस्तैद रहने को कहा।

निर्वाचन आयोग की जवाबदेही की मांग को लेकर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या ।लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस महासचिव एवं सांसद श्रीमती प्रियंका गांधी जी सहित कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं एवं सांसदों के साथ जंतर–मंतर की ओर शांतिपूर्वक बढ़ते समय कथित दुर्व्यवहार एवं लाठीचार्ज की घटना के विरोध में जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में जिलाध्यक्ष चेतनारायण सिंह तथा महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम के नेतृत्व में अयोध्या में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसजनों ने इस दिन को भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिवस बताते हुए निर्वाचन आयोग की जवाबदेही सुनिश्चित करने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की मांग उठाई ।प्रदर्शन के दौरान गांधी पार्क में बड़ी संख्या में कांग्रेसजन एकत्रित हुए। यहां से केंद्र सरकार एवं निर्वाचन आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कचहरी स्थित बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की ओर मार्च निकाला गया ।कचहरी गेट पर तैनात पुलिसकर्मियों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच गहमागहमी हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बलपूर्वक गेट खोलकर कचहरी परिसर में प्रवेश किया और सरकार तथा निर्वाचन आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद कांग्रेसजनों ने बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्लोकतंत्र बचाओश, श्ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दोश सहित विभिन्न नारे लगाते हुए निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा की मांग की। जिला कांग्रेस अध्यक्ष चेतनारायण सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और जवाबदेही सर्वोपरि है। यदि लोकतंत्र के प्रहरी माने जाने वाले संस्थानों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं, तो उनका निष्पक्षता से जवाब दिया जाना चाहिए। शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है और इसकी आवाज को दबाने का कोई भी प्रयास लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई निरंतर जारी रखेगी ।महानगर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम ने कहा कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक अधिकारों और निष्पक्ष निर्वाचन व्यवस्था की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी तथा इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ हुई कथित अभद्रता और लाठीचार्ज की घटना निंदनीय है। निर्वाचन आयोग को अपनी कार्यप्रणाली के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज बनकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी ।कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह एवं जिला प्रवक्ता शीतला पाठकने कहा कि 8 अक्टूबर 2026 को काला दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता, जवाबदेही और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना है। कांग्रेस पार्टी संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर स्तर पर अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी ।पूर्व जिला अध्यक्ष रामदास वर्मा एवं राम अवध पासी ने कहा संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिकता कर्तव्य है ।जिला कांग्रेस प्रवक्ता शीतला पाठक ने बताया कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक सिंह , पीसीसी सदस्य उग्र सेन मिश्रा, अनिल सिंह, अनिल तिवारी, अशोक कुमार सिंह, रुद्र प्रताप सिंह रिशु, रमाशंकर तिवारी, रामकिशोर वर्मा, राजेंद्र प्रसाद, दिलीप गॉड, प्रशांत पांडे, संतोष तिवारी, राजेंद्र कोरी,तौसीफ खान, इरफान खान, तारीक रुदौली, राकेश बंसल, नीलम गौतम, कविंद्र साहनी, नाजिश फातिमा, दयावती, पुष्पा देवी, भगवान बहादुर शुक्ला,सुशांत पांडे, संतोष तिवारी, सुधीर प्रदीप, तेजबली पांडे, करमराज यादव शेर बहादुर दुबे शिव बहादुर दुबे महिपाल सिंह रामकरण कोरी अकबर अली मेजर अशोक कुमार सिंह मनोज कुमार श्रीनिवास तिवारी सुनील सिंह रमाकांत गुप्ता दयाशंकर तिवारी विश्व प्रकाश मिश्रा रमाशंकर तिवारी शैलेंद्र मणि पांडे राकेश तिवारी विजय यादव विनायक घर द्विवेदी रामेंद्र त्रिपाठी बसंत प्रहलाद माझी शैलेंद्र विक्रम सिंह यशवीर सिंह अश्वनी सिंह मधुर धर्मेंद्र सिंह फास्टर रामराज निषाद विकास पाल सिंह शालिग्राम प्रजापति जिओ हैदर कविंद्र साहनी, राकेश तिवारी रजनीश शर्मा रामेंद्र मोहन मिश्रा पप्पू रामनाथ शर्मा विजय यादव हरजीत सिंह सलूजा अशोक कनौजिया अरुण साहू नाजिश फातिमा दयावती विकास मिश्रा राजकुमार सोनी सेवादल महानगर अध्यक्ष बसंत मिश्रा अशोक कुमार शर्मा कल शर्मा सुरेंद्र प्रताप सिंह राष्ट्रीय छात्र संगठन महानगर अध्यक्ष जय प्रताप गुप्ता आदि उपस्थित रहे।

जनसंख्या दूसरे चरण की तैयारी तेज 'फील्ड ट्रेनरों के प्रशिक्षण का तृतीय बैच का शुभारंभ

सुलतानपुर। जनपद में फील्ड ट्रेनरों के प्रशिक्षण के तृतीय बैच का तीन दिवसीय प्रशिक्षण के एन आई सिविल इंजीनियरिंग विभाग में सुबह नौ बजे से शुरू हुआ। तीन चरण के प्रशिक्षण में कुल 88 फील्ड ट्रेनर जनपद की पांचों तहसील में प्रगणको व पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। कस्बा स्थित कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान में मास्टर ट्रेनरों विजय कुमार चतुर्वेदी भूपेन्द्र प्रताप ने प्रतिभागियों को जनगणना प्रक्रिया 40विंदुओ के बारे बारीकियों की जानकारी दी। इसमें फील्ड ट्रेनरों ने वास्तविक स्थितियों में जनगणना प्रक्रिया, प्रगणकों की जिम्मेदारी, फॉर्म भरने और डिजिटल तरीके से आंकड़े इकट्ठा करने व दर्ज करने का अभ्यास किया। ये फील्ड ट्रेनर अब तहसील में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देंगे, ताकि जनगणना तय नियमों व समय से पूर्ण हो सके। दूसरे चरण की जनगणना में 16 से 30 नवंबर 2026 तक स्व– गणना, 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक जनसंख्या गणना और 5 से 9 जनवरी 2027 तक रिवीजन का कार्य सम्पन्न होगा। इस मौके पर फील्ड ट्रेनर रणवीर सिंह राहुल राष्ट्रवादी अखिलेश मिश्रा सुचित्रा नंद चतुर्वेदी राज कुमार तिवारी राजेश सिंह अम्बरीष पाण्डेय सहित 28 फील्ड ट्रेनर उपस्थित रहे।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान मे अवरोध से पेंशनर्स खफा

जौनपुर। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पेंशनर्स कार्यालय पर हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जनपदअध्यक्ष सी बी सिंह ने बताया कि पेंशनर्स को देय चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक का भुगतान शासन स्तर से 30 सितम्बर तक आफ लाईन एवं 01अक्टूबर से आफ लाइन तथा आन लाइन दोनो की स्पष्ट व्यवस्था की गयी है। इसके वाद भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर पर 30सितम्बर तक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक को तकनिकी परीक्षण के लिए 25 सितम्बर से कार्यालय मे लेना बन्द कर दिया गया है, जो शासनादेश के बिरूध्द है। इस अव्यवस्था को शीध्र दूर नही किया गया, तो पेंशनर्स एसोसिएशन सांगठनिक कार्यवाही , अनशन,धरना–प्रदर्शन करने को विवश होगा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पूर्व अध्यक्ष एवं संरक्षक राकेशकुमार श्रीवास्तव केन्द्रीय आठवे वेतन आयोग के संकल्प पत्र मे पेंशनर्स के टर्म्स रिफरेन्स को तत्काल सम्मिलित करने की केन्द्र सरकार से मांग किए। सदस्यो ने अपने सम्बोधन मे चिकित्सा प्रतिपूर्ति मे आ रही कठिनाई से अवगत कराया । पेंशनर्स की मांग को शीघ्र पूरी करने की सरकार से मांग करते हुए अगले संघर्ष के लिए तन मन धन से सहयोग का संकल्प व्यक्त किया । ओकांर नाथ मिश्र, कान्ति सिंह, मोराली सिंह, कृष्ण कुमार त्रिपाठी.चन्द्रशेखर सिंह, कंचनसिंह, गोपालओश्रीवास्तव,राजेश कुमार श्रीवास्तव, अशोक कुमार मिश्र,डॉक्टर भारत यादव,वी वी सिंह, दिनेश चन्द्र सिंह, फूल चन्द्र नाविक, दसरथ राम आदि ने सम्बोधित किया। संचालन जिलामन्त्री कृपाशंकर उपाध्याय ने किया।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 - 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार-पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।